उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 अंक 11 1-15 जून 2021 ₹ 20/-

सेंट्रल विस्टा परियोजना के कारण चार मस्जिदों पर विवाद

- बीपीएससी में 88 मुस्लिम उम्मीदवार सफल
- नाफ्ताली बेनेट बने इजरायल के नए प्रधानमंत्री
- तालिबान का अफगानिस्तान के नौ जिलों पर कब्जा
- लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाने की मांग

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक-प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी-51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए-102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

सेंट्रल विस्टा परियोजना के कारण चार मस्जिदों पर विवाद 04
बिहार लोक सेवा आयोग में 88 मुस्लिम उम्मीदवार सफल 06
अजमेर दरगाह के नजराने पर विवाद 07
माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की 24 करोड़ की संपत्ति सील 08
संघ द्वारा हिंदू मुस्लिम सद्भावना स्थापित करने का अभियान 09
अयोध्या की मस्जिद स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अहमद शाह के नाम 10

विश्व

तालिबान का अफगानिस्तान के नौ जिलों पर कब्जा 11
आतंकी इस्लामिक संगठन बोको हरम प्रमुख की बम धमाके में मौत 12
दिलीप कुमार और राज कपूर के पैतृक मकान पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में 13
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला 14
अफगानिस्तान में फौजी हेलीकॉप्टर तबाह 15

पश्चिम एशिया

नाफ्ताली बेनेट बने इजरायल के नए प्रधानमंत्री 16
अरबों से इजरायल की दोस्ती कराने में अमेरिका फिर सक्रिय 18
विदेशियों के हज करने पर प्रतिबंध 19
इजरायली विमानों द्वारा सीरिया पर बमबारी 20
पश्चिम अफ्रीका में इस्लामिक आतंकवादियों का हमला 21

अन्य

लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाने की मांग 22
वजीरिस्तान में बारूदी सुरंगों के कारण पलायन 22
ईरानी जहाज डूबा 23
मदरसा के लिए जमीन आवंटन करने की मांग 23
नागरिकता कानून के नोटिफिकेशन को उच्च न्यायालय में चुनौती 23

सारांश

चुनाव समीप आते ही कुछ शरारती तत्व जानबूझकर मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए नित-नए शोशे छोड़ रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर यह आरोप लगाया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कारण चार ऐतिहासिक मस्जिदों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद इस मुद्दे पर अन्य मुस्लिम नेता भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाने तक की धमकी दे दी है। इससे पूर्व भी उत्तर प्रदेश में यही तत्व अवैध ढांचों को मस्जिद बताकर प्रशासन द्वारा उनको ध्वस्त किए जाने के मामले को तूल देने में जुटे हुए हैं। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य साम्प्रदायिकता की ज्वाला को भड़काकर चुनावों में वोट बटोरना है।

काफी समय से कुछ मुस्लिम संगठन यह दुष्प्रचार करते आ रहे हैं कि मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और उनकी उपेक्षा की जा रही है। मगर हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं के जो परिणाम घोषित किए गए हैं उससे इस दावे की कलई पूरी तरह से खुल जाती है। इन परीक्षाओं में ८८ मुस्लिम उम्मीदवारों ने बाजी मार ली है। यदि केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के आकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो भी इस बात की पुष्टि होती है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सरकारी नौकरियों के लिए चुने जाने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

अफगानिस्तान का मामला दिन-प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। अमेरिकी सरकार ने अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद जिन लोगों को यह आशा थी कि विदेशी सैनिकों के अफगानिस्तान से वापस चले जाने के बाद वहां पर स्थिति सुधरेगी उनकी इन आशाओं पर पानी फिर गया है। विश्व के दोनों जिहादी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट और तालिबान बड़ी तेजी से अफगानिस्तान में अपने पैर फैला रहे हैं। अमेरिका को यह आशा थी कि तालिबान तुर्की के सैनिकों को मुसलमान होने के कारण अफगानिस्तान में रखने पर तैयार हो जाएंगे। मगर तालिबान ने कहा है कि तुर्की क्योंकि नाटो का सहयोगी देश है इसलिए उसके सैनिकों को भी अन्य विदेशी सैनिकों के साथ अफगानिस्तान खाली करना पड़ेगा। देखना यह है कि अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है।

इजरायल में सत्ता परिवर्तन हो गया है। 15 वर्षों के बाद इजरायल की सत्ता बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ से निकल गई है। इजरायल के नए प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट को कट्टरवादी यहूदी माना जाता है। कभी वे नेतन्याहू के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री हुआ करते थे। खास बात यह है कि आठ राजनीतिक दलों का जो नया गठबंधन वहां सत्ता में आया है। उसमें पहली बार अरब भी शामिल किए गए हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि नाफ्ताली सिर्फ एक वोट के अंतर से सत्ता में आए हैं। इसलिए उनकी सरकार कितनी देर टिक पाएगी इस संबंध में कोई भी भविष्यवाणी करना काफी कठिन होगा।

सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष भी विदेशियों के हज यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे उन 45 हजार भारतीय हज यात्रियों को घोर निराशा हुई है जो हज यात्रा की पूरी तैयारी कर चुके थे। सऊदी सरकार की नई नीति के तहत अब सिर्फ सऊदी नागरिक या वहां पर रहने वाले विदेशी मूल के लोग ही हज यात्रा या उमरा कर सकेंगे। इस फैसले से सऊदी सरकार को भारी आर्थिक नुकसान भी होगा। क्योंकि हर वर्ष विश्व भर के 20 लाख मुसलमान हज यात्रा करने के लिए वहां जाते हैं और उनसे एक बहुत मोटी रकम सऊदी सरकार से प्राप्त होती है।

सेंट्रल विस्टा परियोजना के कारण चार मस्जिदों पर विवाद

इंकलाब (4 जून) ने लिखा है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना की आड़ में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली चार मस्जिदों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है और साथ ही यह धमकी दी है कि अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो हम दस दिनों के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। दूसरी ओर दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक टीम ने इन मस्जिदों का सर्वे किया है और अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंप दी है। इंडिया गेट और उसके आसपास के क्षेत्रों में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत काम चल रहा है और इस क्षेत्र में चार मस्जिदें हैं जहां पर पांचो वक्त की नमाज होती है। इनमें इंडिया गेट के समीप स्थित मस्जिद जाब्ता गंज, उपराष्ट्रपति के निवास स्थान परिसर में स्थित मस्जिद और कृषि भवन तथा उद्योग भवन के समीप स्थित मस्जिदें शामिल हैं। ये चारों मस्जिदें ऐतिहासिक हैं। अमानतुल्लाह का कहना है कि इनमें से तीन मस्जिदों का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है।

समाचारपत्र ने कहा है कि कृषि भवन के समीप स्थित मस्जिद को गिराए जाने की संभावना है। क्योंकि यह सड़क के मध्य में स्थित है। अमानतुल्लाह का कहना है कि केन्द्र सरकार को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या ये चारों मस्जिदें परियोजना के तहत हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हम इन मस्जिदों पर किसी भी कीमत पर आंच नहीं आने देंगे। बोर्ड के एक अधिकारी मोहम्मद इमरान ने कहा कि हमने अपना सर्वे पूरा

कर लिया है और अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गेट के जाब्ता गंज मस्जिद के इमाम का कहना है कि इन मस्जिदों को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों का संरक्षण करना बोर्ड की जिम्मेवारी है और बोर्ड अपना काम करेगा।

रोजनामा सहारा (10 जून) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष महमूद मदनी ने इन मस्जिदों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए केन्द्रीय आवास मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर कहा है कि किसी भी स्थिति में इन ऐतिहासिक मस्जिदों को संरक्षण प्रदान किया जाए। जमीयत उलेमा के महामंत्री मौलाना हमीदुद्दीन कासमी ने भी हाल ही में इस क्षेत्र का दौरा किया था और इन मस्जिदों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी।

इंकलाब (5 जून) के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इंडिया गेट पर स्थित मस्जिद जाप्ता गंज के इमाम मौलाना असदउल्लाह फलाही को तुरंत उनके पद से हटा दिया है और कहा है कि वे बोर्ड के अभियान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वे मनमाने बयान दे रहे हैं। मौलाना ने कहा है कि मैने अपना बयान एक पत्रकार को दिया था उसके बाद मुझे कोई भी बयान देने से वक्फ बोर्ड ने रोक दिया है। उसके बाद मैंने कोई बयान नहीं दिया। मगर इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने बिना कोई कारण बताए मुझे इमामत से हटा दिया है जो कि गैरकानूनी है।

इंकलाब (12 जून) के अनुसार दिल्ली की मस्जिदों के अस्तित्व के बारे में सोशल मीडिया और समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित होने के बाद देश भर के मुसलमानों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। कानपुर में इमामों की एक बैठक में कहा गया है कि अगर इन मस्जिदों के अस्तित्व को कोई खतरा पैदा हुआ तो देश के मुसलमान उनकी हर कीमत पर रक्षा करेंगे। क्योंकि ये मस्जिदें हमारी प्राचीन विरासत का हिस्सा हैं।

टिप्पणी : जिन चारों मस्जिदों के बारे में विवाद शुरू हुआ है उनमें से कम-से-कम तीन मस्जिदें काफी प्राचीन हैं। जहां तक जाब्ता गंज मस्जिद का संबंध है नई दिल्ली को राजधानी घोषित करने से पहले इस क्षेत्र में जाब्ता गंज नामक एक गांव बसा हुआ था और यह मस्जिद उसी का हिस्सा था। अंग्रेजों ने इस मस्जिद को गिराने के बजाय उसे इंडिया गेट के दोनों ओर बनाई गई वाटर चैनलों में शामिल करके यथावत रखा था। यह मस्जिद 300 वर्ष पुरानी है और यह दो मंजिला है। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण नवाब नजीबुद्दौला के पुत्र जाब्ता खान ने शाह आलम के शासनकाल में करवाया था। जहां तक कृषि भवन के समीप गोल चक्कर में बनी बांग्ला मस्जिद का संबंध है यह भी लगभग साढ़े तीन सौ वर्ष पुरानी है। इस मस्जिद की विशेषता यह है कि इसकी छत चपटी है। इस तरह की मस्जिदों का निर्माण आमतौर पर बंगाल में किया जाता रहा है। दिल्ली में तीन मस्जिदें इस मॉडल की हैं। जहां तक दो अन्य मस्जिदों का संबंध है वह 1911 के बाद की बनी हुई हैं। इनमें से एक मस्जिद उद्योग भवन में अभी भी नमाज अदा की जाती है। जबकि उपराष्ट्रपति निवास में जो मस्जिद है उसका निर्माण देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने करवाया था। वे उस समय इस बंगले में निवास करते थे। इस समय इस मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाती है।

बिहार लोक सेवा आयोग में 88 मुस्लिम उम्मीदवार सफल

इंकलाब (8 जून) के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इन परीक्षाओं में 1454 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इनमें मुसलमानों की संख्या 88 है। जो मुस्लिम उम्मीदवार इन परीक्षाओं में सफल हुए हैं उनमें बिहार सरकार के अल्पसंख्यक आयोग द्वारा चलाए जा रहे कोचिंग और मार्गदर्शन देने वाले संस्थान के 49 उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसमें आसमा खातून का नाम भी है। इनका चयन बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ है। इस संस्थान ने इस वर्ष 106 मुस्लिम उम्मीदवारों को इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की मुफ्त तैयारी करवाई गई थी और इस तैयारी के लिए सरकार ने अनेक विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त की थीं। 2013 तक इस संस्थान में केवल बिहार पुलिस सेवाओं के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती थी। इसके बाद क्योंकि उसके परिणाम आशाजनक रहे थे इसलिए बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने यह प्रशिक्षण अन्य सेवाओं के लिए भी देना शुरू किया। इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले छात्रों को रहने, खाने और पुस्तकों की नि:शुल्क सुविधा बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

रोजनामा सहारा (7 जून) के अनुसार इस परीक्षा में जो मुस्लिम छात्र सफल हुए हैं उनमें से 13 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और 17 जामिया मिलिया इस्लामिया में शिक्षा प्राप्त हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि इस वर्ष जो उम्मीदवार चुने गए हैं उनमें से मुस्लिम उम्मीदवारों का अनुपात लगभग सात प्रतिशत है। जबकि बिहार की जनसंख्या में मुसलमानों का अनुपात 14 प्रतिशत है।

इस संदर्भ में यह बात भी उल्लेखनीय है कि देश के प्रशासकीय ढांचे में मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनाने के लिए एक दर्जन से अधिक मुस्लिम संगठनों द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए मुस्लिम छात्र एवं छात्राओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण तथा उनके आवास तथा भोजन की भी मुफ्त व्यवस्था की जाती है। ज़कात फाउंडेशन द्वारा देश भर में एक दर्जन स्थानों पर ऐसे केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। यही कारण है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों का अनुपात दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।

अजमेर दरगाह के नजराने पर विवाद

इंकलाब (8 जून) के अनुसार राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह के नजराने को वसूल करने पर खादिमों के दो गुटों में विवाद शुरू हो गया है। अब दरगाह कमेटी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में भी कुछ खादिम यात्रियों से नजराना मांग रहे हैं। इस पर दरगाह कमेटी ने लिखित रूप से खादिमों के अंजुमनों से स्पष्टीकरण मांगा है। मगर अभी तक उनमें से किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दरगाह कमेटी के प्रबंधक अशफाक हुसैन के अनुसार श्रद्धालुओं से नजराना वसूलने का हक सिर्फ दरगाह कमेटी को है। उन्होंने पुलिस कप्तान को एक पत्र भेजकर उनसे पूछा है कि जब लॉकडाउन में दरगाह बंद है और वहां पर पुलिस का पहरा है तो ऐसे हालात में श्रद्धालु दरगाह के अंदर कैसे दाखिल हो रहे हैं? दरगाह कमेटी ने अंजुमन सैयद जादगान और अंजुमन शेख जादगान को नोटिस भेजा था, जिसमें एक वायरल वीडियो भी भेजा गया था। उस वायरल वीडियो में खादिमों को श्रद्धालुओं से नजराना वसूल करते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर खादिमों का कहना है कि उन्हें दरगाह के अंदर आने वाले यात्रियों से नजराना वसूल करने का हक है। दरगाह कमेटी जानबूझकर उन पर गलत आरोप लगा रही है। ■

माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की 24 करोड़ की संपत्ति सील

इंकलाब (10 जून) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के खिलाफ जोरदार अभियान चला रही है। मऊ पुलिस ने दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के दशई पोखरा स्थित मुख्तार अंसारी की 24 करोड़ की जमीन को सील कर दिया है। हालांकि जमीन पर बनी मस्जिद को पुलिस ने जब्त नहीं किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से मुख्तार अंसारी और उसके समर्थकों में हलचल मच गई है। प्रशासन के अनुसार यह जमीन राम-जानकी ट्रस्ट की है और इस भूमि पर मुख्तार अंसारी और उसके गुंडों ने कब्जा कर रखा है। राम-जानकी का मंदिर मऊ नगर में दशई पोखरा के समीप स्थित है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार मुख्तार अंसारी ने डेढ़ हेक्टेयर भूमि पर कब्जा करके उसकी फर्जी रजिस्टरी अपनी मां के नाम पर करवाई थी और वहां पर उसने विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू करवा दिया था। 2016 में छोटेलाल नामक एक व्यक्ति ने मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जे की ओर जिलाधिकारी का ध्यान दिलाया था। इस पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस के अनुसार विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। वह 1988 से अपराध जगत का कुख्यात व्यक्ति है। उसके खिलाफ 49 फौजदारी मुकदमे विचाराधीन हैं। आपराधिक गतिविधियों से उसने जो धन कमाया था उससे उसने यह भूमि खरीदी थी। इस भूमि पर उसके दो मकान हैं जिनके मूल्य का अनुमान दो करोड़ लगाया जाता है। जबकि एक अन्य मकान निर्माणाधीन है। जिला मजिस्ट्रेट ने माफिया गिरोह एक्ट के तहत सात जून 2021 को एक आदेश जारी करके इस संपत्ति को सरकारी कब्जे में लेने का निर्देश दिया था। उसके बाद इस संपत्ति को कब्जे में लिया गया है।

इंकलाब (9 जून) के अनुसार हरदोई जिला के एक बदनाम शराब माफिया और समाजवादी पार्टी के नेता सुभाष पाल की ढ़ाई करोड़ की संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली है। सुभाष पाल के खिलाफ गुंडा एक्ट और अवैध शराब बेचने आदि के अनेक आरोप हैं। जिलाधिकारी के आदेश के बाद पुलिस ने सुभाष पाल की गैस एजेंसी को भी कुर्क कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि सुभाष पाल एक हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसने अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत हत्या और अपहरण से की थी। इसके बाद उसने मिलावटी शराब बेचकर करोड़ों रुपये कमाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उसके गिरोह से संबंधित अन्य व्यक्तियों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है। सुभाष पाल समाजवादी पार्टी की टिकट पर दो बार विधान सभा का चुनाव लड़ चुका है।

एक अन्य समाचार के अनुसार पुलिस ने गोरखपुर के माफिया प्रदीप सिंह की 50 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। उसके खिलाफ दस से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने जो संपत्ति जब्त की है उसमें भूमि और उस पर बनी दुकानें, होटल और तीन मंजिला मकान शामिल हैं।

संघ द्वारा हिंदू मुस्लिम सद्भावना स्थापित करने का अभियान

इंकलाब (6 जून) के अनुसार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की पुस्तक 'वैचारिक समन्वय-एक व्यावहारिक पहल' को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (दिल्ली) के संयोजक हाफिज मोहम्मद साबरीन को सौंपते हुए कहा कि यह एक ऐसी पुस्तक है जो देश में हिंदू-मुसलमान के बीच उत्पन्न मतभेदों को दूर करेगी और दोनों को पास लाने में एक पुल की भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि हमें इस बात की प्रसन्नता है कि समाज में डॉ. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद जैसी हस्तियां मौजूद हैं जो कि न केवल समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना चाहते हैं बल्कि वे समाज को आपस में जोड़ने और एक दूसरे का साथ देने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक की कुछ प्रतियां लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को भी वितरीत की जाएंगी।

इस अवसर पर हाफिज मोहम्मद साबरीन ने कहा कि यह पुस्तक उस समय सामने आई है जब ऐसी पुस्तकों की बहुत जरूरत है। इस पुस्तक में जो सामग्री दी गई है उसने वर्तमान भारत के राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में छिपी हुई हकीकतों को समझने की ईमानदार कोशिश की है। साबरीन ने कहा कि इस पुस्तक का अध्ययन करने से अनेक बातें साफ हो जाएंगी और लोगों को मालूम होगा कि उन्हें जानबूझकर गलतफहमियों का शिकार बनाया गया है। इसलिए इन गलतफहमियों को दूर करना बेहद जरूरी है। लेखक ने पुस्तक में भारत के उदीयमान भविष्य की तस्वीर पेश की है। इस पुस्तक का विधिवत विमोचन आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत करेंगे।

अयोध्या की मस्जिद स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अहमद शाह के नाम

मुंबई उर्दू न्यूज (7 जून) के अनुसार बाबरी मस्जिद के बदले में मिली जमीन पर बनने वाली धन्नीपुर की मस्जिद का नाम स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अहमद शाह फैजाबादी के नाम पर रखा जाएगा जो कि 164 वर्ष पहले शहीद हो गए थे। इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि मौलवी अहमद शाह के शहीदी दिवस पर हमने मस्जिद की सारी परियोजनाओं का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मौलवी अहमद शाह हिंदू-मुस्लिम भाईचारे के नायक थे। मौलवी साहब को भारतीय इतिहास में आज तक वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मस्जिद सराय उनका मुख्यालय थी। फैजाबाद की यह जगह आज भी उनके नाम की याद दिलाती है। स्वतंत्रता संग्राम में एक गद्दार के हाथों मौलवी की हत्या हो गई थी। अंग्रेजों ने उनके शरीर और सिर को दो विभिन्न स्थानों पर दफन किया था ताकि लोग उनकी कब्र को मकबरा न बना सकें।

इतिहासकार अफजल अहमद खान का कहना है कि हालांकि अनेक अंग्रेज लेखकों ने अपनी पुस्तकों में मौलाना अहमद शाह को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्हें अवध का सबसे बड़ा बागी करार दिया था। मगर इसके बावजूद भारतीय इतिहास में उनका कोई जिक्र तक नहीं मिलता। लेखक रामशंकर त्रिपाठी का कहना है कि वे भले ही मुसलमान थे लेकिन वे फैजाबाद की धार्मिक एकता और गंगा-जमुनी संस्कृति के भी प्रतीक थे। 1857 के युद्ध में वे नाना साहब और आरा के कुंवर सिंह के साथ मिलकर लड़े थे। मौलवी अहमद शाह ने चिनहट के युद्ध में अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाए थे और उनकी प्रेरणा से 22वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी थी। मौलवी चाहते थे कि शाहजहांपुर जिले के एक जमींदार भी उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हों। मगर जब वे इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए उसके किले में गए तो उसने अंग्रेजों के इशारे पर उनकी हत्या कर दी और उनका सिर अंग्रेज सेनापति को पेश करके भारी जागीर और इनाम हासिल किया।

इंकलाब (9 जून) के अनुसार धन्नीपुर मस्जिद का नाम शहीद मोहम्मद अहमद शाह के नाम पर रखने के लिए शहीद शोध संस्थान ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया है।

तालिबान का अफगानिस्तान के नौ जिलों पर कब्जा

इंकलाब (7 जून) के अनुसार तालिबान ने यह दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान के पांच महत्त्वपूर्ण जिलों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह दावा किया है कि जाबुल, अरघंज खवा और नूरिस्तान पर तालिबान फौज ने कब्जा कर लिया है और सरकारी फौजों को वहां से भगा दिया है। इसके अतिरिक्त तालिबान ने तलावा बार्फक के चार अन्य जिलों में भी अपनी हुकूमत करने का दावा किया है। सरकारी प्रवक्ता तारिक आर्यन ने कहा है कि इन पांच जिलों से सरकारी सेना एक नीति के तहत हटी है। अफगान मीडिया का दावा है कि तालिबान ने इन क्षेत्र की सभी सरकारी सेक्युरिटी पोस्टों पर कब्जा कर लिया है और इस हमले में दोनों ओर से कई लोग मारे गए हैं।

इंकलाब (3 जून) के अनुसार अमेरिकी सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी सेना के सबसे बड़े अड्डे बाग्राम को 20 दिनों में खाली करके अफगानिस्तान सरकार को सौंप दिया जाएगा। बाग्राम अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इसका निर्माण 1980 में सोवियत यूनियन ने किया था। वाशिंगटन में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को निकालने का काम तेजी से कर रहा है। अब तक छह सैनिक अड्डे खाली करने के बाद अफगान सरकार को सौंपे जा चुके हैं। आधी अमेरिकी सेना और सैनिक उपकरण वापस भेजे जा चुके हैं और अनेक ऐसी चीजों को ध्वस्त कर दिया गया है जिनको वापस ले जाना संभव नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने कांधार एयरफिल्ड को भी खाली करके अफगान फौज को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगियों की सेनाएं अब अफगानिस्तान में नहीं रहेंगी किंतु 30 देशों के गठबंधन की ओर से अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए वहां की सेना को हर तरह की सहायता को जारी रखा जाएगा।

आतंकी इस्लामिक संगठन बोको हरम प्रमुख की बम धमाके में मौत

इंकलाब (8 जून) के अनुसार बोको हरम और इस्लामिक स्टेट की सेनाओं के बीच हुई झड़प में बोको हरम के प्रमुख अबुबकर शेकाऊ की मौत हो गई है। इस सिलसिले में एक वीडियो संवाद समिति 'रॉयटर्स' को प्राप्त हुआ है। इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि शेकाऊ उसके हमले में मारा गया है। जबकि जानकार सूत्रों का दावा है कि उसने आत्महत्या की है। बोको हरम के प्रवक्ता का कहना है कि उनका नेता एक धमाके मे मारा गया है। उसकी मौत 18 मई को नाइजीरिया के जंगलों में हुई थी। बताया जाता है कि जब इस्लामिक स्टेट के आतंकी उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे थे तो उसने बारूद से भरी जैकेट में धमाका करके आत्महत्या कर ली। बोको हरम 2009 से एक दर्जन अफ्रीकी देशों में सक्रिय है। उसके तार आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि बोको हरम ने दस हजार लोगों का अपहरण करके उन्हें गुलाम के रूप में विभिन्न देशों में बेचा था और तीस हजार से अधिक लोगों की हत्या की थी। पहले बोको हरम का संपर्क इस्लामिक स्टेट से था मगर बाद में उसने उससे संबंध विच्छेद करने के बाद अलकायदा और अल अंसार नामक आतंकवादी संगठनों का हाथ थाम लिया था।

बोको हरम का दावा है कि जब उसका नेता अपने एक अड्डे में था तो एक अन्य संगठन आईएसडब्लयूएपी ने अपने सैनिकों को उस पर हमला करने के लिए भेजा। इस हमले में बोको हरम के सारे सैनिक मारे गए। मगर अबु बकर शेकाऊ किसी तरह से वहां से फरार होने में सफल हो गया। मगर बाद में उसका सुराग लगा लिया गया और जब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो उसने आत्महत्या कर ली। नाइजीरिया सरकार ने कहा है कि वह इस सारे मामले की अपने स्तर पर जांच कर रही है।

दिलीप कुमार और राज कपूर के पैतृक मकान पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में

इंकलाब (3 जून) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के पुरातत्व विभाग ने भारतीय फिल्म स्टार दिलीप कुमार और राज कपूर के पैतृक घरों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। पाकिस्तान सरकार संग्रहालय के रूप में इसे विकसित कर रही है। दिलीप कुमार का मूल नाम युसूफ खान है और वे पेशावर के मूल निवासी हैं। जबकि कपूर परिवार जिसमें पृथ्वीराज कपूर और उनके बेटे राज कपूर आदि शामिल थे वे भी पेशावर के ही मूल निवासी हैं। इससे पूर्व पेशावर के डिप्टी कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इन दोनों मकानों को पुरातत्व विभाग को सौंपने की घोषणा की थी। पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉ. अब्दुल समद ने कहा कि दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर के परिवार का उपमहाद्वीप के फिल्म उद्योग में विशेष स्थान है। इन दोनों के पैतृक घर देखभाल नहीं होने के कारण जर्जर हो रहे थे। इसलिए सरकार ने अपनी इस विरासत को सुरक्षित रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर के वंशजों से वे संपर्क में हैं और इन दोनों फिल्म स्टारों के परिवारों ने इनसे संबंधित विभिन्न वस्तुएं इन संग्रहालयों को भेंट करने का आश्वासन दिया है। हमारा लक्ष्य पेशावर का बॉलीवुड से नाता जोड़ना है। उन्होंने कहा कि इन दोनों मकानों पर जिन लोगों का कब्जा था उन्हें इनका मुआवजा दे दिया गया है।

युसूफ खान का घर मोहल्ला खुदादाद में है। इसका निर्माण उनके बाप व दादा ने करवाया था। इसके लिए 72 लाख रुपये कीमत अदा की गई है। जबकि कपूर परिवार की हवेली की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपये अदा की गई है। ये दोनों हवेलियां पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में स्थित है। 2016 में जब कपूर परिवार की हवेली को उसके वर्तमान पाकिस्तानी मालिक ने गिराकर

उसकी जगह नया मकान बनाने का प्रयास किया था तो उस पर पाकिस्तानी समाचारपत्रों में जबर्दस्त हंगामा हुआ था, जिस पर ध्वस्त किए जाने का काम उसे अधूरा छोड़ना पड़ा था। मगर फिर भी इस मकान का काफी हिस्सा तोड़ दिया गया था। अवामी नेशनल पार्टी के शासनकाल में भी इस संपत्ति को अधिगृहित करने की कोशिश की गई थी मगर कीमत का विवाद हो जाने के कारण यह संभव नहीं हो सका था। अक्टूबर 2015 में सरकार ने पेशावर उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि इन फिल्म स्टारों के मकानों को संग्रहालय के रूप में संरक्षित रखने की योजना को उन्होंने खटाई में डाल दिया है। जब यह समाचार अखबारों में छपा तो उस पर पूरे पाकिस्तान में जबर्दस्त बवाल मचा और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा।

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला

अवधनामा (3 जून) के अनुसार पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के दो कस्बों तुर्बत और मारवाड़ में पाकिस्तानी सेना की फ्रंटियर कोर के चौकियों पर प्रतिबंधित पृथकतावादी संगठन बलूच लिब्रेशन आर्मी ने हमला किया और चार सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जबकि आठ जख्मी हुए। बलूच लिब्रेशन आर्मी आजाद बलूचिस्तान के लिए काफी देर से सशस्त्र संघर्ष कर रही है। पाकिस्तानी सेना इसके अनेक नेताओं को गोली से उड़ा चुकी है, जिनमें अकबर खान बुगती आदि प्रमुख हैं।

पाकिस्तान सेना के लोक संपर्क विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार पृथकतावादियों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। पहली घटना मारवाड़ के इस्माइल दरगाह के समीप तब हुई जब उन्होंने फ्रंटियर कोर के सैनिकों को निशाना बनाया। इस हमले में चार सैनिक अधिकारी मारे गए और छह घायल हो गए। इसके बाद

पृथकतावादियों ने एक अन्य चौकी पर हमला किया। दस घंटे तक जंग जारी इस हमले में पांच पृथकतावादी मारे गए और आठ घायल हो गए।

जबकि एक अन्य घटना में सेना के एक वाहन पर रिमोर्ट कंट्रोल द्वारा धमाका किया गया जिसमें दो सैनिक घायल हो गए। प्रतिबंधित पृथकतावादी बलूच संगठन लिब्रेशन आर्मी के प्रवक्ता जुनैद बलूच ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के पंजे से आजाद होने का बलूचों का यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा और हम आखिरी दम तक पाकिस्तानी तानाशाहों के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना के छह अधिकारी मारे गए हैं और इस हमले में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। पिछले महीने तीन जगह पर पाकिस्तानी सेना और पृथकतावादी संगठनों के बीच झड़पें हुई थीं, जिनमें पाकिस्तानी सेना के चार अधिकारी मारे गए और छह घायल हुए थे।

अफगानिस्तान में फौजी हेलीकॉप्टर तबाह

इत्तेमाद (10 जून) के अनुसार अफगानिस्तान में भूमि पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाते हुए दस अमेरिकी सैनिक मारे गए और सोलह जख्मी हो गए। जबकि एयर फोर्स के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तीन अमेरिकी मारे गए। कहा जाता है कि इस हेलीकॉप्टर को तालिबान ने अपना निशाना बनाया था।

इंकलाब (3 जून) के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और जलालाबाद सहित अनेक शहरों में बम धमाकों के कारण कम-से-कम तीस लोग मारे गए। अफगानी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि जिहादियों ने दो बसों को भी अपना निशाना बनाया है, जिसमें कम-से-कम 20 यात्री मारे गए और दस घायल हो गए। जबकि अस्पताल के सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या 32 बताई जाती है। जलालाबाद में हुए बम धमाकों में दो लोग मारे गए और दस जख्मी हुए। तालिबान ने पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें कम से कम 4 पुलिस अधिकारी मारे गए और पांच घायल हो गए।

नाफ्ताली बेनेट बने इजरायल के नए प्रधानमंत्री

हमारा समाज (15 जून) के अनुसार इजरायल की राजनीति में नया धमाका हुआ है। इजरायली संसद ने 12 वर्ष से सत्तारूढ़ बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटा दिया है और अरब पार्टी की सहायता से 49 वर्षीय कट्टरवादी यहूदी नाफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री बने हैं। संसद के 60 सदस्यों ने नए मंत्रिमंडल के पक्ष में मत दिया और 59 ने इसके विरोध में मतदान किया। इस दौरान एक सदस्य अनुपस्थित भी रहा। नए सत्तारूढ़ गठबंधन में आठ दल शामिल हैं। इनमें देश की 21 प्रतिशत अरब जनसंख्या की प्रतिनिधि पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट भी शामिल है। नाफ्ताली मंत्रिमंडल में 27 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिनमें नौ महिलाएं भी शामिल हैं। इजरायल के इतिहास में इससे पूर्व इतनी बड़ी संख्या में कभी महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। महिला मंत्रियों में पांच अरब मूल की हैं। इनमें से दो का संबंध मोरक्को और तीन का संबंध इराक से है। नई सरकार के गठन के समय तय किए गए फार्मूले के तहत नाफ्ताली 2023 में अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे और उनकी जगह 57 वर्षीय येर लापिद प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे।

इजरायली संसद में इससे पूर्व संसद अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। 120 सदस्यों में से 67 ने मिकी लेवी को अपने मत दिए। गत सप्ताह इस नए गठबंधन के गठन के बाद यह तय हो गया था कि नेतन्याहू के लिए अब चौथी बार देश का प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं होगा। वे 2009 से इजरायल के प्रधानमंत्री हुए थे। इससे पहले वे 1996-1999 तक इजरायल के प्रधानमंत्री रह चुके

थे। वे कुल 15 वर्षों तक सत्ता में रहे। नए प्रधानमंत्री इजरायल के पहले कट्टर यहूदी प्रधानमंत्री हैं जो कि अधिकृत पश्चिमी किनारे क्षेत्र में यहूदियों की और बस्तियां बनाने के पक्ष में हैं और वे इस फिलिस्तीनी क्षेत्र को इजरायल में स्थाई रूप से विलय करना चाहते हैं। हालांकि उनके गठबंधन में शामिल यूनाइटेड अरब लिस्ट उसका विरोधी है।

इजरायल में 23 मार्च को हुए संसदीय चुनाव में कोई भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सका था। अभी केवल एक वोट के अंतर से नई सरकार का गठन हुआ है। यूनाइटेड अरब लिस्ट के नेता मंसूर अब्बास ने आशा व्यक्त की है कि नए प्रधानमंत्री फिलिस्तीनियों के साथ न्याय करेंगे और अरबों तथा यहूदियों के बीच संबंध सुधारने का प्रयास करेंगे। मंत्रिमंडल में एक अरब राजनेता इस्सावी फरेज को भी शामिल किया गया है। उनकी पार्टी इजरायल में रहने वाले अरब नागरिकों को समान अधिकार देने की समर्थक रही है।

दैनिक सियासत (1 जून) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने मोर्चा बना लिया है। इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री यामिना पार्टी के प्रमुख नाफ्ताली ने येश अतिद पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की घोषणा की है। नाफ्ताली ने कहा कि अगर वे सरकार बनाने में विफल रहे तो देश में पांचवीं बार चुनाव होंगे। इजरायल की 120 सदस्यीय संसद में नाफ्ताली की पार्टी के सिर्फ छह सदस्य हैं और वे किंगमेकर बन गए हैं। नेतन्याहू ने इस गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इजरायली जनता के साथ इस दशक का यह सबसे बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि नाफ्ताली ने जनता से यह वायदा किया था कि वे भविष्य में लापिद से हाथ नहीं मिलाएंगे। मगर अब उन्होंने स्वयं इस वायदे को तोड़ दिया है।

सियासत (2 जून) के अनुसार इजरायल के राष्ट्रपति ने विपक्षी गठबंधन को नई सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है।

सियासत (15 जून) ने इजरायल के नए प्रधानमंत्री के बारे में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा है कि कट्टरवादी नाफ्ताली बेनेट इजरायल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वे फिलिस्तीनी सरकार बनाने के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने सिर्फ एक वोट के बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। ऐसी स्थिति में सरकार को बनाए रखना उनके लिए कठिन होगा। इजरायल के नए प्रधानमंत्री का जन्म अमेरिका में हुआ था और वे वहां से पलायन करके इजरायल आए थे। इजरायल की सेना में वे कई वर्षों तक काम कर चुके हैं। 1999 में बेनेट ने एक अमेरिकी स्टार्टअप धोखाधड़ी विरोधी सॉफ्टवेयर कंपनी स्थापित की थी। यह कंपनी उन्होंने अमेरिका को 2005 में 145 मिलियन डॉलर में बेच दी थी। इसके बाद उन्होंने व्यापार के क्षेत्र को छोड़कर राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था। उस समय बेंजामिन नेतन्याहू विपक्षी नेता थे और नाफ्ताली उनके प्रमुख सहायक थे। वे येशा काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए। इस काउंसिल का कार्य फिलिस्तीन अधिकृत क्षेत्रों में यहूदी बस्तियों को विस्तार देना है। जब नेतन्याहू सत्ता में आए तो उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया और वे शिक्षा तथा रक्षा मंत्री भी बने।

दिसंबर 2018 में वे ज्यूज होम संगठन से अलग हो गए और न्यूराइट ग्रुप की स्थापना की। अप्रैल 2019 के चुनाव में उन्हें एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई।

अरबों से इजरायल की दोस्ती कराने में अमेरिका फिर सक्रिय

सियासत (12 जून) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी इजरायल के बारे में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों का ही अनुसरण कर रहे हैं। बाइडेन का प्रयास यह है कि अधिक से अधिक अरब देश इजरायल को मान्यता देकर उसके साथ दोस्ती स्थापित करें। यही कारण है कि अमेरिका ने अपनी इस नीति को लागू करने के लिए हर हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया है। मध्य पूर्व में जब से इजरायल बना है उसे अरब राष्ट्रों का कभी सहयोग प्राप्त नहीं रहा और अरब उसका हमेशा विरोध करते आ रहे हैं। ट्रम्प प्रशासन ने गत वर्ष इजरायल और चार अरब देशों के बीच संबंध स्थापित करवाने के लिए दबाव के साथ-साथ विभिन्न प्रलोभनों का भी सहारा लिया था। प्रारम्भ में बाइडेन की नीति इजरायल और अरब के बीच तटस्थ बने रहने की थी। मगर बाद में हालात को देखते हुए उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया और अब वे ट्रम्प की नीति का ही अनुसरण कर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन का यह प्रयास है कि अरब देशों में विभाजन पैदा करके इजरायल के समर्थकों की संख्या में वृद्धि की जाय।

अमेरिकी सूत्रों के अनुसार इस बात की संभावना है कि कुछ और मुस्लिम देश इजरायल के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे। अमेरिकी दबाव पर सूडान ने हालांकि इजरायल के साथ शांति संबंध बनाए रखने के बारे में तो समझौता कर लिया था। मगर अभी तक उसने इजरायल के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं। इसलिए अमेरिका ने उसे भारी आर्थिक सहायता की पेशकश की है ताकि वह इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर ले। जॉर्डन भी इस बात का प्रयास कर रहा है कि वह इजरायल के साथ संबंध स्थापित करे। हाल ही में इजरायल और हमास के बीच जो 11 दिन तक युद्ध हुआ था उसके कारण अब इस बात की काफी कम संभावना है कि अमेरिका की यह नीति अरब देशों में सफल हो पाए। क्योंकि मुस्लिम जगत का दृष्टिकोण इस समय इजरायल विरोधी है। पिछले महीने गाजा पट्टी में हुए इजरायली हमलों में 245 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इनमें 66 बच्चे भी शामिल थे। इस हमले के विरोध में अरब देशों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है और अरब जनभावना इस वक्त इजरायल के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में अमेरिका को अपनी इजरायल समर्थक नीति को लागू करवाने में परेशानी हो रही है। अब तक संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को इजरायल के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर चुके हैं। जबकि सूडान की जनता अब इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का विरोध कर रही है और वह इस संबंध में कई बार उग्र प्रदर्शन कर चुकी है। ट्रम्प प्रशासन ने सूडान सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि अगर वह इजरायल को मान्यता प्रदान कर देता है तो उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका वापस ले लेगा।

हाल ही में बाइडेन प्रशासन ने इजरायल में पूर्व अमेरिकी राजदूत डेनियल शापिरो को इजरायल और अरब देशों के बीच दोस्ती की नीति के विस्तार की जिम्मेवारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि

चार और अरब देशों ने इस बात का संकेत दिया है कि वे इजरायल के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने जिन अरब देशों को रक्षा सामग्री सप्लाई करने में हिचकिचाहट प्रकट की थी अब वह उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि वे इजरायल के साथ संबंधों को सुधारें और जिन रक्षा उपकरणों की सप्लाई इन देशों को करने पर बाइडेन प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया था वह उसे वापस ले लेगा।

विदेशियों के हज करने पर प्रतिबंध

इत्तेमाद (13 जून) के अनुसार सऊदी सरकार ने यह घोषणा की है कि इस वर्ष केवल सऊदी नागरिकों और सऊदी अरब में रहने वाले विदेशी मूल के लोगों को ही हज करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही हाजियों की संख्या भी साठ हजार तक सीमित कर दी गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह फैसला कोरोना महामारी और उसके नए-नए रूपों के प्रसार को देखते हुए किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के उन लोगों को ही हज करने की अनुमति होगी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई हो। प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला इस्लामिक शरा को समक्ष रखकर किया गया है। क्योंकि इस्लामिक शरा का मूल लक्ष्य यह है कि लोगों के जीवन को कोई खतरा न हो। इसलिए इस वर्ष हज को सीमित करने का फैसला किया गया है। हज के लिए इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र जमा करवाने होंगे और सिर्फ उन्हीं को हज की अनुमति दी जाएगी जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हों और दो बार वैक्सीन लगवा चुके हों।

उप हज मंत्री डॉ. अब्दुल फतह मशाथ ने कहा है कि इस फैसले की सूचना विश्व के सभी

इस्लामिक देशों को दे दी गई है और उन्होंने इसका स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा कि विदेशियों को उमरा करने की भी अनुमति नहीं होगी।

इंकलाब (14 जून) के अनुसार सऊदी अरब के इस फैसले से भारत के 45 हजार लोगों को घोर निराशा हुई है, जिन्होंने हज करने के लिए हज कमेटी के पास अपने नाम दर्ज करवा रखे थे। भारत के हज मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को अंत तक यह आशा थी कि सऊदी सरकार भारतीय हज यात्रियों को हज करने की अनुमति दे देगी। इसलिए उन्होंने भारत से हज यात्रा के इच्छुक व्यक्तियों को यह सलाह दी थी कि वे पूरी तैयारी करें।

हमारा समाज (15 जून) ने एक संपादकीय में सऊदी अरब के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि पहले दुनिया भर के बीस लाख मुसलमान हज किया करते थे। कोरोना महामारी के कारण अगर हज यात्रा के दौरान महामारी भीषण रूप ले लेती तो उससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। समाचारपत्र ने यह आशा व्यक्त की है कि सऊदी सरकार मक्का व मदीना को महामारी से मुक्त रखने के लिए विशेष प्रबंध करेगी।

इजरायली विमानों द्वारा सीरिया पर बमबारी

इत्तेमाद (10 जून) के अनुसार इजरायल के युद्ध विमानों ने सीरिया के सैनिक ठिकानों पर बमबारी की जिसमें कम-से-कम 10 लोग मारे गए। सीरिया सरकार ने आरोप लगाया है कि इजरायली जहाजों ने लेबनान के हवाई अड्डों से उड़ान भरी थी और दमिश्क पर बमबारी की। सीरिया के रक्षा तंत्र के हरकत में आ जाने के बाद इजरायली जहाजों को वहां से भागना पड़ा। सीरिया के मानवाधिकार संगठन के प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस हमले में सीरियाई सेना और मलेशिया के पांच-पांच अधिकारी मारे गए हैं। इजरायल ने इस हमले के बारे में कोई भी समाचार नहीं दिया है।

सीरिया सरकार ने दावा किया है कि इजरायल की ओर से दागे गए कुछ मिसाइलों को उन्होंने रास्ते में ही गिरा दिया था, जिसके कारण वे हानि पहुंचाने में विफल रहे। मगर दमिश्क में अनेक धमाकों की आवाज सुनी गई है जो मिसाइलों के हमलों की बताई जाती है। मीडिया ने इस बात का भी दावा किया है कि सीरिया के विमान भेदी तोपों ने इजरायली विमानों पर धुआंधार गोले दागे। उनका यह भी कहना है कि इजरायली हमले से होम्स के क्षेत्र में भारी मात्रा में जान व माल का नुकसान हुआ है। सीरियाई फौज के अस्त्र-शस्त्र के भंडारों को भी इजरायली सेना ने अपना निशाना बनाया था, जिसके कारण कई विमान तबाह हो गए। सीरिया ने इजरायली हमलों को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित कर रखा है।

इस्लामिक आतंकवादियों का हमला

इंकलाब (6 जून) के अनुसार पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में पिछले कुछ वर्षों के बाद इस्लामिक आतंकवादी हमलों में कम-से-कम 100 लोग मारे गए। आतंकियों ने सुलहान नामक कस्बे पर हमला किया। मरने वालों में महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। इस हमले की शुरुआत सरकार समर्थक मिलिशिया के अड्डों से हुई। इस मिलिशिया का गठन वहां की सरकारी सेना की मदद के लिए दो वर्ष पूर्व किया गया था। सरकारी प्रवक्ताओं ने यह संकेत भी दिया है कि मरने वालों की संख्या में और भी वृद्धि हो सकती है। इस क्षेत्र में अल शबाब और अल अंसार नामक इस्लामिक आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। आक्रमणकारियों ने सारे कस्बों में आग लगा दी जिससे सैकड़ों मकान और दुकानें जल गईं। गत सप्ताह भी आतंकवादियों ने बारह लोगों की सामूहिक हत्या कर दी थी। 2015 के बाद से इस्लामिक देश बुर्किना फासो को इस्लामिक आतंकवाद के संगठन सपोर्ट इस्लाम एंड मुस्लिम और इस्लामिक स्टेट आदि संगठनों की ओर से भी निरंतर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक इन हमलों में 13 हजार लोग मारे जा चुके हैं और बीस लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं।

अन्य

लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाने की मांग

इत्तेमाद (4 जून) के अनुसार केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल को वापस बुलाने की मांग की गई है। लक्षद्वीप अरब सागर में एक द्वीप समूह है, जिसके निवासी कई दिनों से प्रशासक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का विरोध कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने सदन में यह प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केरल और लक्षद्वीप के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। अब राजनीतिक कारणों से प्रशासक वहां के परंपरागत जनजीवन में अनुचित हस्तक्षेप कर रहे हैं। विरोधियों को दबाने के लिए पहली बार इस क्षेत्र में गुंडा एक्ट का इस्तेमाल किया गया है।

अखबार ने लिखा है कि इस क्षेत्र के निवासियों का मूल भोजन गोमांस है। मगर प्रशासक ने गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

हाल ही में उन्होंने दो बच्चों से अधिक परिवार वाले व्यक्तियों के किसी भी चुनाव में खड़े होने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। यह लोगों के व्यक्तिगत जीवन में अनुचित हस्तक्षेप है। इस क्षेत्र में व्याप्त जनाक्रोश को देखते हुए केन्द्र सरकार को वर्तमान प्रशासक को तुरंत वापस बुला लेना चाहिए।

वजीरिस्तान में बारूदी सुरंगों के कारण पलायन

अवधनामा (4 जून) के अनुसार पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान के एक गांव में बारूदी सुरंगों के विस्फोट के कारण तीन बच्चे मारे गए और दो घायल हो गए। कहा जाता है कि ये बारूदी सुरंग आतंकवादियों और पृथकतावादियों के खिलाफ चलाए गए सैनिक अभियान के सिलसिले में इस क्षेत्र में अनेक जगहों पर लगाई गई थीं। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले एक दशक में इन बारूदी सुरंगों के फटने से कम-से-कम 200 लोग मारे जा चुके हैं और 300 लोग अपंग हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना के लोक संपर्क विभाग ने यह दावा किया है कि कबाइली इलाकों में बिछाई हुई 48 हजार से ज्यादा बारूदी सुरंगों को नकारा बना दिया गया है ताकि लोग उनका शिकार न बनें। मगर अभी हजारों बारूदी सुरंगें दबी हुई हैं। इन सुरंगों के कारण कई क्षेत्रों में स्थानीय आबादी ने पलायन शुरू कर दिया है।

ईरानी जहाज डूबा

इंकलाब (3 जून) के अनुसार ईरान का एक बहुत बड़ा जहाज अचानक आग लगने के बाद समुद्र में डूब गया है। यह जहाज ईरान ने ब्रिटेन से खरीदा था और यह सबसे बड़ा जहाज था जिसे 40 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। इस जहाज को बचाने और आग पर काबू पाने के लिए ईरानी अधिकारी 24 घंटे तक कोशिश करते रहे मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उसमें सवार सभी कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस जहाज के डूबने से ईरान के तेल सप्लाई को जबर्दस्त धक्का लगा है।

मदरसा के लिए जमीन आवंटन करने की मांग

कलाब (11 जून) के अनुसार शिया नेता सैयद कल्बे जवाद नकवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके उनसे मांग की है कि जिस सरकारी भूमि पर सुल्तान उल मदरसा बना हुआ है वह मदरसे के नाम अलॉट की जाए। मौलाना ने कहा है कि यह मदरसा मेरे दादा ने बनवाया था और अभी इस मदरसे में सैकड़ों शिया छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1911 में अंग्रेज सरकार ने यह भूमि 100 वर्ष की लीज पर शियाओं को दी थी और इस भूमि पर मेरे दादा ने इस मदरसे का निर्माण करवाया था। तब से इस मदरसे का संचालन हुसैनाबाद ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। अब क्योंकि लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है इसलिए इस भूमि को सरकार हुसैनाबाद ट्रस्ट के नाम अलॉट करे।

नागरिकता कानून के नोटिफिकेशन को उच्च न्यायालय में चुनौती

मुंबई उर्दू न्यूज (2 जून) के अनुसार भारत सरकार ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के जिलों में रहने वाले अफगानी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी गैरमुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए याचिकाएं दायर करने का जो नोटिफिकेशन भारत सरकार ने दायर किया है उसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि नागरिकता कानून को मुस्लिम लीग ने न्यायालय में चुनौती दी थी जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। केन्द्र सरकार ने न्यायालय में यह सफाई दी थी कि नागरिकता कानून के नियमों का अभी फैसला नहीं हुआ है इसलिए इस पर अभी रोक लगाने की जरूरत नहीं है। मगर अब गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी तौर पर यह नोटिफिकेशन जारी करके इन देशों से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाईयों से नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र तलब किए हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए आश्वासन का खुला उल्लंघन है इसलिए इस नोटिफिकेशन को तुरंत रद्द किया जाए।

RNI No. DELHIN/2017/72722

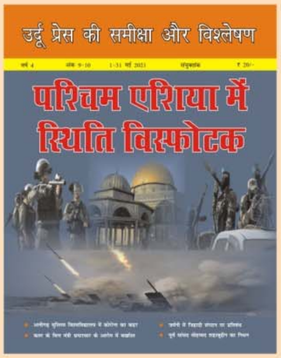

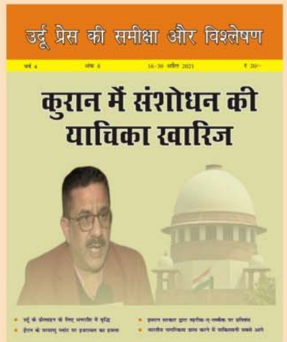

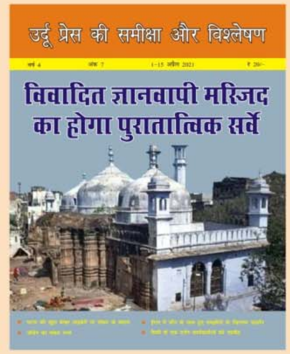

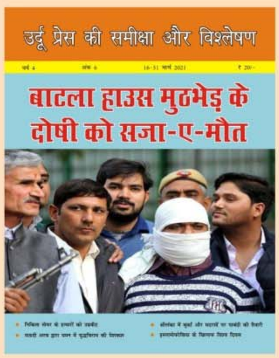

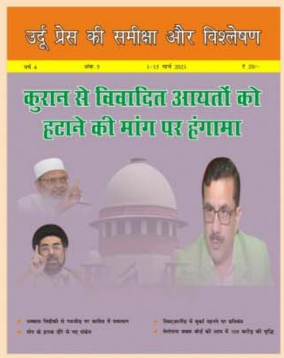

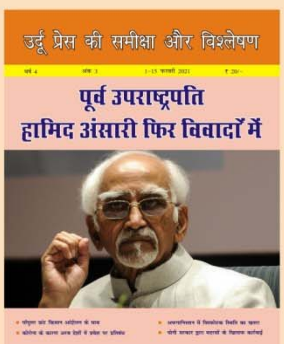

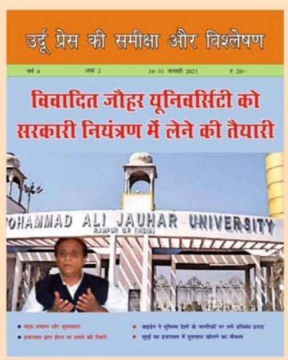

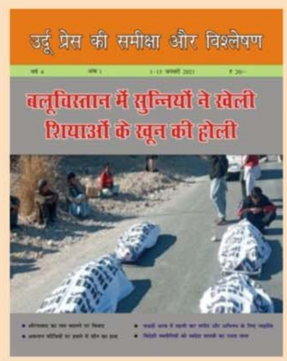

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in